Issue of bonds by CIL

2326. SHRIMATI KAMLA SINHA:
SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that CIL plans to make its maiden issue of Bonds in the next financial year i.e. 1993-94;

(b) if so, what will be the size of the issue;

(c) what is the total resources requirement of CIL for the next fiscal year;

(d) whether any direct bi-lateral credit is being negotiated with World Bank of Canada or Australia or any other foreign country or agency; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JIT KUMAR PANJA): (a) and (b) India Limited has been floating bonds in the market since 1989-90. Every year the Ministry of Finance in consultation with Planning Commission and this Ministry fixes the quantum of resources to be raised through Bonds. For the year 1993-94 this has been fixed at Rs. 400 crores for CIL.

(c) The Planning Commission have fixed the total outlay of CIL for the next financial year 1993-94 at Rs. 1901 crores.

(d) and (e) CIL has been receiving External Assistance directly from Australia and Canada. For the year 1993-94 the assistance expected is:

Australia	Rs. 150.24 crores
Canada	Rs. 22.62 crores

The anticipated external Assistance routed through Budget for the year 1993-94 comprises the following:—

World Bank credit	Rs. 146.62 crores
French credit	Rs. 25.36 crores
German credit	Rs. 2.18 crores
U.K. Grant	Rs. 25.44 crores
Russian credit	Rs. 5.05 crores
	Rs. 204.65 crores

भारत में घाटे में चल रही कोयला खानें

2327. **श्री सोमपाल** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कुल कितनी कोयला खानें हैं इनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितनी खानें घाटे में चल रही हैं;

(ग) इनमें घाटा होने के क्या कारण हैं

(घ) उनमें प्रति वर्ष कोयले का कुल कितना उत्पादन होता है; और

(ङ) इन खानों के बंद हो जाने से कितने मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री अजित कुमार पांजा** : (क) कोल इंडिया लि० (को०इं०लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनकी कुल 449 खान ऐसी हैं जहां कि खनन कार्य किया

जा रहा है । इनका राज्यवार ब्यौरा निम्न है :—

1. बिहार	161
2. पश्चिम बंगाल	110
3. मध्य प्रदेश	111
4. महाराष्ट्र	37
5. उड़ीसा	21
6. असम	5
7. उत्तर प्रदेश	4
जोड़	449

इसके अलावा, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (आंध्र प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन) आंध्र प्रदेश राज्य में 65 खानें चला रही हैं ।

(ख) को.इं.लि. में कुल 449 खानों में से 350 खानें वर्तमान में घाटे में चल रही हैं ।

(ग) इन खानों के घाटे में चलने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) देश के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की लगातार कमी जिसमें सामान्य कोयला उत्पादन के क्रियाकलापों में विस्तृत रुप से रुकावट आती है जिसके परिणामस्वरुप कोयला उत्पादन प्रभावित होता है ।

(2) अनेक कोयला उत्पादन खानें अत्याधिक पुरानी हैं जहांकि कोयला भंडार भी लगभग समाप्त हो गए हैं जिससे वहां कोयले के उत्पादन में कठिनाई होती है ।

(3) भूमिगत खानों में श्रमिकों की बहुलता होती है, अत: उनका प्रतिव्यक्ति प्रतिपाली उत्पादन कम है ।

(4) अनेक भूमिगत खानों में भू-गर्भीय अड़चनें आती रहती हैं जिससे सामान्य खनन क्रियाकलापों में कठिनाई होती है ।

(5) भूमि की अनुपलब्धता से वर्तमान ओपेनकास्ट उत्खनन का विस्तार नहीं हो पाता है और साथ ही नई ओपेनकास्ट तथा भूमिगत खानें भी खोली जा सकती हैं ।

(घ) अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1991–92 के दौरान कोयले का उत्पादन निम्नलिखित रूप में हुआ :—

उत्पादनकर्ता	उत्पादन (मिलियन टन में)
को.इं.लि.	204.14
सि.को.कं.लि.	20.58
अन्य	4.56
जोड़	229.28

(ङ) सरकार को इन घाटे में चलने वाली खानों को बंद किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अत: वर्तमान में किसी श्रमिक के बेरोजगार हो जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Arrears due to Maharashtra State Electricity Board

2328. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what is the amount of arrears due on the Maharashtra State Electricity Board an account of the sale of Coal as on 1st March, 1993.

(b) what steps are being taken in order to recover the said arrears;

(c) whether any dispute on a part of such arrears exists between the parties; and

(d) if so what is the disputed amount?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) to (d) The total outstanding dues to Co-